



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2017/Ext.] □ CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2017 (MAGHA 18, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 फरवरी, 2017

संख्या 20 / 15 / 2009–4 जे०जे०(1).— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39), की धारा 28 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियम, 1966, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियम, 1966, में नियम 19 में, “₹1,50,000/- (केवल एक लाख पचास हजार रुपये),” अक्षर, चिह्न, शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर ₹3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये),” अंक, चिह्न, शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

राम निवास,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT**

**Notification**

The 7th February, 2017

**No. 20/15/2009-4JJ(1).**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Legal Services Authority Rules, 1996, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2017.
2. In the Haryana State Legal Services Authority Rules, 1996, in rule 19, for the letters, figures, signs, brackets and words “₹ 1,50,000/- (one lakh fifty thousand rupees only)”, the letters, figures, signs, brackets and words “₹ 3,00,000/- (three lakh rupees only), shall be substituted.”

RAM NIWAS,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Administration of Justice Department.

54992-C.S.-H.G.P., Chd.